

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,  
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून

दिनांक 15 जुलाई, 2014

विषय:- वन विभाग के अनुदान सं०-31 (अनुसूचित जनजाति उप योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर की योजना "बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण" में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 की आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-318/XXVII(1)/2014 दि० 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश सं० 80/अ०मु०स०/पी०एस०/2014-15 दि० 23 अप्रैल, 2014 में दिये गये निर्देशों के आलोक में एवं उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के प०सं० नि०-1976अ/2-36(अनु०जनजाति उप योजना), दि० 13 जून, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के आयोजनागत पक्ष की "बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण" राज्य सेक्टर की योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये प्राविधानित आय-व्ययक ₹ 1,40,00,000/- (₹ एक करोड़ चालीस लाख मात्र) के सापेक्ष ₹ 1,37,33,000/- (₹ एक करोड़ सैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-318/XXVII(1)/2014 दि० 18 मार्च, 2014 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदों में व्यय किया जाय।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्चोरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।
4. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
5. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
6. आपके निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
7. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी०एम०-प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
8. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
9. आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय शासन को सूचित किया जाय।
11. स्वीकृति कार्यों हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि धनराशि की बचत होती है तो बचत की धनराशि यथासमय शासन को सूचित की जाय।



1750(B)

शासनादेश संख्या X-2-2014-12(28)2012 दि 15 जुलाई, 2014 का संलग्नक अनुदान सं०-31  
 अनुसूचित जाति उप योजना) की आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना "बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं  
 वनों का संरक्षण" (राजस्व पक्ष) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपलब्ध बजट के सापेक्ष मानक  
 मद/प्रभाग/वन मार्गवार वित्तीय/भौतिक स्वीकृति

मानक मद-24 - वृहद् निर्माण एवं मानक मद-29 अनुरक्षण

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र० सं०	प्रभाग का नाम	योजना - 2408-01-796-0400 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण																				
		मानक मद-24 - वृहद् निर्माण															मानक मद-29 - अनुरक्षण					
		वृक्षारोपण कार्य		अग्रिम मृदा कार्य		पेशा उत्पादन हेतु हिमालियन नेटम (कण्डाली) का रोपण		मृदा एवं जल संरक्षण कार्य		चैकडेन/ रिटोनिंग वाल निर्माण		परकुलेशन टैंक		अरब/पैदल मार्गों का सुचारु/ जीर्णोद्धार		योग	वृक्षारोपण अनुरक्षण		लेण्टाना/ कालाबांस/ श्यामाघास उन्मूलन		योग	कुल योग
		भौतिक (₹0)	वित्तीय	भौतिक (₹0)	वित्तीय	भौतिक (₹0)	वित्तीय	भौतिक (₹0)	वित्तीय	भौतिक (₹0)	वित्तीय	भौतिक (₹0)	वित्तीय	भौतिक (₹0)	वित्तीय	वित्तीय	भौतिक (₹0)	वित्तीय	भौतिक (₹0)	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	पिथौरागढ़ वन प्रभाग	0	0	0	0	50	850	180	2154	0	0	0	0	4	1080	4084	140	749	220	684	1700	5517
2	तराई पूर्वी वन प्रभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	150	0	0	150	150
3	भूमि संरक्षण कालसी	30	324	35	1400	0	0	0	0	80	960	0	0	38.5	773	3457	346	1850	0	0	1850	5307
4	भूमि संरक्षण अलकनंदा	50	744	0	0	50	850	8	100	20	240	42	420	3.5	105	2459	50	300	0	0	300	2759
	योग -	80	1068	35	1400	100	1700	188	2254	100	1200	42	420	46	1958	10000	566	3049	220	684	3733	13733
	उपलब्ध आय-व्ययक															10000					3733	13733

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ एक करोड़ सैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)

(मनाज चन्दन)  
अपर सचिव



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 1750(B) X-2-2014-12(28)/2012

अलोटमेंट आई डी - S1407310061

अनुदान संख्या - 031

आवंटन पत्र दिनांक -14-Jul-2014

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक

2406 - बानिकी तथा वन्य जीवन

01 - बानिकी

796 - जनजाति क्षेत्र उप योजना

04 - बहुउद्देशीय व्रक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण

00 - सिविल एवं सोयम वनों का विकास (राज्य सेक्टर)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत् निर्माण कार्य	0	10000000	10000000
29 - अन्तरक्षण	0	3733000	3733000
	0	13733000	13733000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

13733000